भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1561

मंगलवार, 29 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएम एकता मॉल योजना

1561. श्री रामप्रीत मंडलः
श्री कौशलेन्द्र कुमारः
श्रीमती लवली आनंदः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उन राज्यों और पर्यटन स्थलों के नाम क्या हैं जहाँ पीएम एकता मॉल योजना के अंतर्गत अब तक 27 मॉल का चयन और अनुमोदन किया गया है;

(ख) सरकार द्वारा प्रत्येक पीएम एकता मॉल को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत मॉल की चयन प्रक्रिया के संबंध में निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): सभी राज्यों को केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित पीएम एकता मॉल (यूनिटी मॉल) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि देशभर के ओडीओपी उत्पादों (एक जिला, एक उत्पाद), भौगोलिक संकेतक (जीआई) उत्पादों और अन्य हस्तशिल्प वस्तुओं को प्रोत्साहन दिया जा सके और इनकी बिक्री की जा सके। इस प्रस्तावित मॉल में प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र और राज्य के लिए अपने ओडीओपी उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए स्थान निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के 'पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता स्कीम 2023-24 (एसएएससीआई)' के भाग-VI (यूनिटी मॉल) के तहत सभी राज्यों में पीएम एकता मॉल के निर्माण के लिए 5000 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। इस स्कीम के अंतर्गत, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की सिफारिश पर व्यय विभाग ने 27 राज्यों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अनुमोदित किया है। स्वीकृत/जारी की गई निधि का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

क्रम सं.	**राज्य**	**वे स्थान जहां पीएम एकता मॉल का निर्माण किया जा रहा है**	**डीओई द्वारा स्वीकृत राशि, वित्त वर्ष 2023-24 (करोड़ रुपए में)**
1	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	172
2	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर	188
3	असम	गुवाहाटी	226
4	बिहार	पटना	212.689
5	छत्तीसगढ़	रायपुर	200.77
6	गोवा	चिंबेल	100
7	गुजरात	सूरत	202
8	हरियाणा	करनाल	155
9	हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला	132
10	झारखंड	रांची	162.92
11	कर्नाटक	मैसूर	192.99106
12	केरल	तिरुवनंतपुरम	120
13	मध्य प्रदेश	उज्जैन	284
14	महाराष्ट्र	नवी मुंबई	195.136
15	मणिपुर	इंफाल	149
16	मेघालय	न्यू शिलांग	132
17	मिजोरम	आइजोल	127
18	नागालैंड	चुमुकेदिमा	145
19	ओडिशा	भुवनेश्वर	187.12
20	पंजाब	अमृतसर	159
21	राजस्थान	जयपुर	202
22	सिक्किम	गंगटोक	106
23	तमिलनाडु	चेन्नई	223
24	तेलंगाना	हैदराबाद	202
25	त्रिपुरा	अगरतला	114
26	उत्तर प्रदेश	आगरा, लखनऊ और वाराणसी	370.247
27	उत्तराखंड	हरिद्वार	136
	कुल		**4795.87306**

(ग): व्यय विभाग द्वारा जारी एसएएससीआई दिशानिर्देशों में प्रत्येक राज्य में एक एकता मॉल की स्थापना के लिए 5000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है, जिसे मुख्य रूप से राज्य की राजधानी में 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर स्थापित किया जाएगा। इन दिशानिर्देशों में संबंधित राज्य की वित्तीय राजधानी या किसी प्रमुख पर्यटन केंद्र में यूनिटी मॉल की स्थापना पर विचार करने का भी प्रावधान है। इस स्कीम के लिए 5,000 करोड़ रुपए की राशि विनिर्धारित की गई है। यह निधि राज्यों को 'पहले आओ पहले पाओ' आधार पर प्रदान की जाएगी। बड़ा राज्य होने के नाते, उत्तर प्रदेश राज्य को आबंटित बजट के भीतर 3 एकता मॉल बनाने की छूट दी गई है। इस मॉल के लिए भूमि राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है या भूमि अधिग्रहण की लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

*****